अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

112 Emergency Response Support System — One India, One Emergency Number 112

रजि.न.34300/80 | संख्या 08 | श्री विजय पुरम, गुरूवार , 08 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत एफएसक्यूएआई के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु पात्र संभावित उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए ईओआई जारी

प्रासंगिक विवरणों के साथ आवेदन 20 जनवरी तक जमा करना अनिवार्य

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना (एफएसक्यूएआई) के तहत एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु पात्र संभावित उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है।

कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन या संस्था, जो केवल वाणिज्यिक खाद्य परीक्षण उद्देश्यों के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना चाहता है, वह दिशा–निर्देशों के खंड–2 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन पात्र होगा। शेष पृष्ठ 4 पर

दक्षिण अण्डमान में मसाला प्रवाह के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ज़िला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

मसाला प्रवाह पहल के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज़िला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की एक बैठक 7 जनवरी, 2026 को दक्षिण अण्डमान ज़िले के उपायुक्त कक्ष में आयोजित की गई। यह बैठक कृषि विभाग द्वारा श्री अर्जुन शर्मा (आईएएस), उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

मसाला प्रवाह को 2,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली एक पाँच वर्षीय कार्ययोजना (2025–2030) के रूप में संरचित किया गया है, जिसका उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मसाला फसलों के समग्र विकास को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित करना है। यह पहल क्षेत्र विस्तार, क्लस्टर विकास तथा मूल्य संवर्धन के माध्यम से मसाला फसलों के शुरू से अंत तक विकास पर केंद्रित है, ताकि द्वीपों के किसानों के लिए एक सतत मसाला अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके। इस योजना को काली मिर्च, असली दालचीनी, जायफल, तेजपत्ता एवं लौंग जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जो द्वीपों की कृषि–जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं। रोपण की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ को शामिल करते हुए अंचल स्तरीय टीमों का गठन किया जा रहा है, जो पौधों की जीवित शेष पृष्ठ 4 पर

माननीय सांसद ने द्वीपों में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के शीघ्र संचालन का आग्रह किया

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सांसद श्री बिष्णु पद राय ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से सीजीएचएस वेलनेस सेंटर व दवाखाने के शीघ्र संचालन का आग्रह किया। सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सांसद ने बताया कि नवंबर, 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्णय के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि केन्द्रशासित प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, मौजूदा स्वास्थ्य ढांचा और मानव संसाधन का उपयोग करके सीजीएचएस वेलनेस सेंटर चालू किया जा सकता है, बिना नई पोस्ट बनाने या वित्त मंत्रालय पर अतिरिक्त भार डाले।

ऐतिहासिक पदोन्नतियों से पुलिस समुद्री बल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ वर्ष

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की पुलिस समुद्री बल (पीएमएफ), जो तटीय सुरक्षा, समुद्री गश्त, निगरानी तथा केंद्र शासित प्रदेश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए समर्पित एक विशेषीकृत इकाई है, ने वर्ष 2025 के दौरान एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक उपलब्धि हासिल की है।

पुलिस समुद्री बल की उत्पत्ति वर्ष 1957 में गठित एक छोटे पुलिस कोस्ट गार्ड के रूप में हुई थी। दशकों के दौरान यह बल एक पेशेवर रूप से सुसज्जित और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में विकसित हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी में भारत की समुद्री सीमाओं को घुसपैठ, अवैध शिकार, तस्करी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री खतरों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रहा है।

पीएमएफ इकाई के गठन के बाद पहली बार, इकाई के भीतर से अधिकारियों के पदों पर पदोन्नतियाँ दी गई हैं, जो इसके संस्थागत विकास और परिपक्वता का एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत चार (4) हेड कांस्टेबलों को उप–निरीक्षक (सब–इंस्पेक्टर) के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो पुलिस मरीन फोर्स में उप–निरीक्षक पद पर की गई पहली पदोन्नतियाँ हैं। विवरण इस प्रकार है:

- तीन (3) हेड कांस्टेबल (सीकनी) को उप–निरीक्षक (मास्टर) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
- एक (1) हेड कांस्टेबल (ग्रीसर) को उप–निरीक्षक (इंजन ड्राइवर) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, इकाई के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व ढांचे को और सुदृढ़ करते हुए एक (1) उप–निरीक्षक (मास्टर) को निरीक्षक (मास्टर) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

सभी पदोन्नतियाँ अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से की गई हैं।

पुलिस समुद्री बल समुद्री सुरक्षा, तटीय एवं द्वीपीय निगरानी, तस्करी विरोधी अभियानों, खोज एवं बचाव कार्यों, आपदा प्रतिक्रिया तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्रीय जल में अवैध गतिविधियों की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुभवी एवं तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों की उच्च पदों पर पदोन्नति से बल की कमान, नियंत्रण तथा समग्र परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है। शेष पृष्ठ 4 पर

मेजर जनरल अजय फिरोज़ शाह ने अण्डमान तथा निकोबार कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार संभाला

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

मेजर जनरल अजय फिरोज़ शाह ने 7 जनवरी, 2026 को अण्डमान तथा निकोबार कमान (एएनसी) के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने यह कार्यभार विशिष्ट सेवा मेडल (वीएसएम) से सम्मानित रियर एडमिरल बिप्लब होता से संभाला। जून, 1991 में द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 14वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त करने वाले इस जनरल अधिकारी की वर्तमान नियुक्ति से पूर्व वे मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड (मुख्यालय एआरटीआरएसी) में मेजर जनरल जनरल स्टाफ (प्रशिक्षण) (एमजीजीएस) (प्रशिक्षण) (ब्रेवो), के रूप में कार्यरत थे।

मेजर जनरल अजय फिरोज़ शाह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), हायर कमांड कोर्स (एचसीसी) तथा दक्षिण अफ्रीका के नेशनल डिफेंस कॉलेज में नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम के स्नातक हैं। उन्होंने हिमनद क्षेत्रों, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस (सीआई ऑपरेशंस), लाइन ऑफ कंट्रोल (एलसी) तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित विभिन्न परिचालन वातावरणों में सेवाएं दी हैं।

उनकी कमान नियुक्तियों में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान (यूएनआईएफआईएल) के साथ मोबाइल रिज़र्व यूनिट, एक टोही एवं समर्थन बटालियन, एक कॉर्प्स रिज़र्व इन्फैंट्री ब्रिगेड तथा एक माउंटेन डिवीजन का नेतृत्व शामिल है। उनकी प्रमुख स्टाफ नियुक्तियों में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड–1 (जीएसओ–1), सहायक सैन्य सचिव (एएमएस), कर्नल जनरल स्टाफ (उपकरण), आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ (जीओसी–आईएन–सी) के सैन्य सहायक (एमए), एक इन्फैंट्री डिवीजन के कर्नल जनरल स्टाफ तथा एक स्ट्राइक कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ (बीजीएस) के पद शामिल हैं।

कमान मुख्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मेजर जनरल अजय फिरोज़ शाह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रशंसा पत्र दो बार तथा जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ (जीओसी–आईएन–सी) प्रशंसा पत्र तीन बार प्रदान किए जा चुके हैं। व्यापक परिचालन एवं स्टाफ अनुभव के साथ, मेजर जनरल अजय फिरोज़ शाह से इस विशिष्ट संयुक्त सेवा कमान की संयुक्त योजना, समन्वय एवं परिचालन प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है।

पुलिस महानिदेशक ने प्रोथरापुर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नई कमांडो बाधाओं का उद्घाटन किया

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

श्री एच.जी.एस. ढालीवाल (आईपीएस), पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस), प्रोथरापुर में नवनिर्मित 10 कमांडो बाधाओं का उद्घाटन किया। यह द्वीपसमूह में पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में श्रीमती सिंधु पिल्लै ए. (आईपीएस), अपर पुलिस महानिदेशक, श्रीमती गीता रानी वर्मा (आईपीएस), पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), सभी उप पुलिस महानिरीक्षक, श्री उमा शंकर (दानिप्स), प्रधानाचार्य (पीटीएस) सहित अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति ने क्षमता विकास एवं पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति विभाग की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाया। नव विकसित, अत्याधुनिक कमांडो बाधाओं को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वे पुलिस कर्मियों की शारीरिक सहनशक्ति, फुर्ती, सामरिक कौशल तथा समग्र परिचालन तैयारी को सुदृढ़ करें। ये सुविधाएँ नव नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों के साथ–साथ सेवारत कर्मियों के लिए भी लाभकारी होंगी तथा यथार्थपरक एवं परिदृश्य–आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेंगी, जो उभरती कानून–व्यवस्था की चुनौतियों, आपदा प्रतिक्रिया तथा द्वीपसमूह में आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है तथा केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के निरंतर प्रयासों को और मजबूत करती है।

शिक्षा एवं खेल निदेशक ने कार निकोबार में खेलो इंडिया जनजातीय खेल के ट्रायल चरण का निरीक्षण किया

कार निकोबार, 7 जनवरी

शिक्षा और खेल निदेशक श्री विक्रम सिंह ने आज कार निकोबार का दौरा किया और कार निकोबार के लपाती स्थित एसएआई, एसटीसी मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स में चयन ट्रायल्स चरण–1 का निरीक्षण किया। यह ट्रायल्स खेलो इंडिया जनजातीय खेल, प्रथम संस्करण

शेष पृष्ठ 4 पर

पुलिस महानिदेशक द्वारा कयाकिंग एवं कैनोइंग और बॉक्सिंग के लिए दो खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

श्री हरगोबिंदर सिंह ढालीवाल (आईपीएस), पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने 7 जनवरी, 2026 को एपीयू पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स, श्री विजय पुरम में आयोजित औपचारिक समारोह के दौरान खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) का उद्घाटन किया। एपीयू पुलिस लाइन में कयाकिंग एवं कैनोइंग केंद्र का भौतिक रूप से उद्घाटन किया गया, जबकि आईआरबीएन मुख्यालय परिसर, पोर्ट मोट में स्थापित बॉक्सिंग केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। यह पहल द्वीपसमूह में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा युवाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समारोह में श्रीमती सिंधु पिल्लै (आईपीएस), अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती गीता रानी वर्मा (आईपीएस), पुलिस महानिरीक्षक सहित अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की स्वीकृति से, खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के संरक्षण में एक ज़िले के लिए दो खेल विधाओं–एपीयू पुलिस लाइन, श्री विजय पुरम में कयाकिंग एवं कैनोइंग तथा आईआरबीएन मुख्यालय परिसर, पोर्ट मोट में बॉक्सिंग–के लिए की गई है। सभी वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ, जिनमें वित्तीय सहायता, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का अंतिम रूप, समझौता ज्ञापनों का निष्पादन तथा पूर्व चैंपियन एथलीटों (पीसीए)/कोचों की नियुक्ति शामिल है, पूर्ण कर ली गई हैं। खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) दिशानिर्देशों के अनुरूप, प्रत्येक खेल विधा के लिए एक–एक पूर्व चैंपियन एथलीट की नियुक्ति की गई है। खेलो इंडिया योजना एवं एसएआई मानकों के अनुसार 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए आयोजित प्रतिभा पहचान परीक्षणों के माध्यम से कयाकिंग एवं कैनोइंग में 37 प्रशिक्षुओं तथा बॉक्सिंग में 18 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार खेलो इंडिया केंद्रों का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को संरचित, वैज्ञानिक एवं सतत खेल प्रशिक्षण प्रदान करना, उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से भविष्य के चैंपियनों का निर्माण करना है। संवाद के दौरान पुलिस महानिदेशक ने खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षुओं को समर्पण और अनुशासन के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन खेलो इंडिया केंद्रों के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए शुभकामनाओं के साथ हुआ।

कक्षा शिक्षण में प्रौद्योगिकी एकीकरण पर प्रशिक्षण शुरू

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

डॉ. एस. राधाकृष्णन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), गाराचरामा द्वारा 7 जनवरी, 2026 को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार, मिडिल प्वाइंट में "कक्षा शिक्षण में प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाना" शीर्षक से तीन–दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की डिजिटल शैक्षणिक दक्षताओं को सुदृढ़ करना है, ताकि कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन श्रीमती संगीता चंद, प्रधानाचार्या, राज्य शिक्षा संस्थान, डाइट द्वारा किया गया, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने प्राथमिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा शिक्षकों को कक्षा शिक्षण को अधिक रोचक, सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए नवोन्मेषी डिजिटल उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह प्रशिक्षण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), एनसीईआरटी के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिनमें प्रो. इंदु कुमार, प्रमुख, आईसीटी एवं प्रशिक्षण विभाग, डॉ. प्रवीण बॉबी बिंझा, सहायक प्राध्यापक, डॉ. गुलशन मुफीद, पीएमयू, आईसीटी एवं प्रशिक्षण विभाग तथा डॉ. प्राची शर्मा, वरिष्ठ अकादमिक परामर्शदाता शामिल हैं।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के 38 क्लस्टर संसाधन केंद्रों से प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में नामित कुल 76 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल का प्रसार एवं कार्यान्वयन क्लस्टर एवं विद्यालय स्तर पर करेंगे, जिससे व्यापक प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम समन्वयक एवं डॉ. एस. आर. डाइट, गाराचरामा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की व्याख्याता श्रीमती आराधना यादव ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए संक्षिप्त संबोधन प्रस्तुत किया।

यह कार्यक्रम नवोन्मेषी एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपेक्षा रखता है।

समावेशी शिक्षा पर क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

डॉ. एस. राधाकृष्णन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), गाराचरामा, श्री विजय पुरम द्वारा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत "सामान्य शिक्षकों हेतु समावेशी शिक्षा, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम (एफसीईसीडी) पूर्ण किया है" विषय पर तीन दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस कार्यक्रम में नौ शैक्षिक अंचलों के शिक्षकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, श्री विजय पुरम में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की दक्षताओं को सुदृढ़ करना, विविध अधिगम आवश्यकताओं का समाधान करना तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 के प्रावधानों के अनुरूप समावेशी कक्षा शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देना था।

समापन सत्र में श्रीमती संगीता चंद, प्रधानाचार्या, राज्य शिक्षा संस्थान, 'डाइट' मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। अपने संबोधन में उन्होंने समावेशी शिक्षा हेतु प्रतिभागी शिक्षकों की प्रतिबद्धता और पेशेवर कौशल में वृद्धि के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समावेशी शिक्षा केवल एक नीतिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रत्येक शिक्षक की नैतिक एवं व्यावसायिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं रणनीतियों को प्रभावी कक्षा शिक्षण में, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के हित में, लागू करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वयन 'डाइट' के व्याख्याता श्री पवन एस. प्याटी एवं श्रीमती समीरा बेगम द्वारा किया गया, जिन्होंने सत्रों की योजना एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम को मुख्यभूमि से पधारे प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों, जिनमें प्रोफेसर रमा एवं श्रीमती श्रीप्रिया, प्रभारी निदेशक, एनआईईपीवीडी, चेन्नई शामिल थीं, की उपस्थिति से और अधिक समृद्ध बनाया गया।

तीन दिनों के दौरान, कार्यक्रम में केस स्टडी, समूह चर्चा, कक्षा अनुकरण (क्लासरूम सिमुलेशन) तथा चिंतनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सहभागितापूर्ण एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रतिभागियों ने सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने कक्षा अनुभव साझा किए, जिससे कार्यक्रम व्यावहारिक एवं प्रभावशाली बना।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस क्षमता विकास कार्यक्रम का सफल समापन समग्र शिक्षा के अंतर्गत डाइट, गाराचरामा की समावेशी शिक्षा पद्धतियों को सुदृढ़ करने, शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए समतामूलक, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 के दृष्टिकोण को साकार करने के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वार्ड संख्या–15 के डेयरी फार्म स्थित शिव मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण समिति (एएनएसीएस) द्वारा जीबी पंत अस्पताल के ब्लड सेंटर एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से, श्री बी. पद्मनाभम, पार्षद, वार्ड संख्या–15, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से 6 जनवरी, 2026 को शिव मंदिर के निकट, डेयरी फार्म, वार्ड संख्या–15 में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा कुल 21 यूनिट रक्तदान किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह शिविर डॉ. सुब्रत साहा, परियोजना निदेशक, अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण समिति तथा निदेशक, राज्य रक्त आधान परिषद, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम के ब्लड सेंटर एवं अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की तकनीकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि एकत्रित सभी रक्त यूनिटों की रक्त जनित रोगों की जांच विधिवत रूप से की जाए।

'अनिम्स' में एमडी, एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 11 जनवरी को

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स) में एमडी, एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की एमडी व एमएस काउंसलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह काउंसलिंग 11 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।

पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे शेष बचे हुए खाली सीटों के लिए आवेदन करें।

क्र.सं.	विषय	राज्य कोटे की खाली सीटें
1	एनाटॉमी	1
2	बायोकेमिस्ट्री	1
3	माइक्रोबायोलॉजी	1
4	ऑप्थैल्मोलॉजी	1
5	जनरल सर्जरी	–
6	एनेस्थिसियोलॉजी	–
कुल		04

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अनिम्स में एमडी, एमएस पाठ्यक्रमों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट **https://andssw1.and.nic.inaniims** पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार **Google** लिंक **https://forms.gle/WDJpJvfGevPUgab7** के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अनिम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विज़िट करें ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित अपडेट और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।

काउंसलिंग के समय उम्मीदवारों के लिए निर्देश:

1. उम्मीदवारों को रविवार 11 जनवर 2026 को सुबह 9 बजे अनिम्स, न्यू कैंपस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, कार्बाइंस कोव में मौजूद होना अनिवार्य है। उन्हें मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ और सभी दस्तावेज़ों की दो सेट सेल्फ–अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी साथ लानी होगी।
2. सीट आवंटन और दस्तावेज़ों का सत्यापन केवल तब किया जाएगा जब उम्मीदवार स्वयं काउंसलिंग में उपस्थित होंगे। उम्मीदवारों को मेरिट क्रम के अनुसार बुलाया जाएगा और उस समय उपलब्ध सीट प्रदान की जाएगी।

ऐतिहासिक पदोन्नतियों से पुलिस समुद्री बल ——पृष्ठ 1 का शेष

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पुलिस महानिदेशक तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पदोन्नत अधिकारियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि वे अपनी बढ़ी हुई ज़िम्मेदारियों का निर्वहन और अधिक समर्पण, पेशेवर दक्षता, ईमानदारी एवं जनसेवा की भावना के साथ करेंगे।

वर्ष 2025 के दौरान की गई यह पदोन्नति प्रक्रिया पुलिस समुद्री बल के संगठनात्मक विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज़ होगी तथा यह विभाग की कॅरियर प्रगति, कार्मिकों के मनोबल और क्षमता विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शिक्षा एवं खेल निदेशक ने कार निकोबार में ——पृष्ठ 1 का शेष

के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्हें शिक्षा और खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है।

दौरे के दौरान निदेशक ने कार निकोबार में आयोजित फुटबॉल चयन ट्रायल्स की समीक्षा की और राज्य खेल संघ के अधिकारियों/प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध एथलीटों, पीईटी और प्रतिभागी खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने पहले संस्करण के खेलो इंडिया जनजातीय खेल में भाग ले रही टीमों के उद्देश्यों को रेखांकित किया, जो संभावित रूप से फरवरी, 2026 में छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे।

निदेशक ने आगे बताया कि इस वर्ष, जनजातीय खेल मुख्यभूमि पर बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों की टीमें 7 से 8 विभिन्न खेलों (फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी और तैराकी) में भाग लेंगी। प्राथमिक उद्देश्य है कि खिलाड़ियों का चयन केवल कच्ची प्रतिभा और योग्यता के आधार पर किया जाए, ताकि द्वीपों के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के लिए अधिकतम पदक जीत सकें। उन्होंने यह भी बताया कि तीरंदाजी और तैराकी के इवेंट्स दक्षिण अण्डमान में आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश प्रतिभागी लिटिल अण्डमान तथा श्री विजय पुरम से हैं, जबकि फुटबॉल चयन ट्रायल्स कार निकोबार में आयोजित किए जा रहे हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निदेशक ने कहा कि सभी खेलों (फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वेटलिफ्टिंग) के लिए टीमों का चयन खेलो इंडिया जनजातीय खेल में किया जाएगा और उन्होंने सभी पात्र युवाओं से आग्रह किया कि वे ट्रायल्स में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने साथियों को भी उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

दक्षिण अण्डमान में मसाला प्रवाह ——पृष्ठ 1 का शेष

रहने की दर तथा पौध स्वास्थ्य प्रबंधन पर सर्वेक्षण करेंगी। बेहतर वृद्धि एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किसानों को मल्चिंग और शेडिंग जैसी निवारक पौध संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2026–27 के दौरान दक्षिण अण्डमान में 118 हेक्टेयर तथा लिटिल अण्डमान में 101 हेक्टेयर क्षेत्र को मसाला खेती के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष को मुख्यभूमि से रोपण सामग्री की खरीद तथा द्वीपों के भीतर विभागीय फार्मों में मसाला पौध उत्पादन की जानकारी दी गई, जिससे कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जनसंपर्क एवं परामर्श व्यवस्था के तहत, किसान मसाला प्रवाह से संबंधित मार्गदर्शन एवं तकनीकी सलाह कृषि विभाग द्वारा संचालित किसान कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 03192–243434 या टोल–फ्री नंबर 1800–345–1145 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत ——पृष्ठ 1 का शेष

दिशा–निर्देशों के खंड–5 में परिभाषित सहायता के स्वरूप के अनुसार, प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता निम्नलिखित घटकों के लिए प्रदान की जाएगी।

घटक	विवरण
उपकरण	सामान्य क्षेत्र: पात्र उपकरण लागत का 50 प्रतिशत कठिन क्षेत्र/एससी/एसटी/एफपीओ: पात्र उपकरण लागत का 70 प्रतिशत
तकनीकी सिविल कार्य (टीसीडब्ल्यू) और फर्नीचर और फिक्स्चर	आवेदक द्वारा प्रस्तावित व्यय, पात्र लागत का अधिकतम 2 प्रतिशत या 15.00 लाख रुपए, जो भी कम हो
एनएबीएल पंजीकरण शुल्क और सीआरएम	एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए जीएसटी सहित पंजीकरण शुल्क और एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) की एकमुश्त खरीद।
प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस)	प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) एक सॉफ्टवेयर–आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग प्रयोगशाला संचालन और डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित, ट्रैक और दस्तावेज़ करने के लिए किया जाता है। यह नमूना पंजीकरण, परीक्षण आवंटन, परिणाम प्रविष्टि, रिपोर्ट निर्माण, डेटा भंडारण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कार्यों का समर्थन करता है। एलआईएमएस प्रयोगशाला कार्य प्रवाह में सटीकता, पता लगाने की क्षमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और आईएसओ/आईईसी 17025 और एनएबीएल आवश्यकताओं जैसे मानकों के अनुपालन को बनाए रखने में मदद करता है।

दिशा–निर्देशों के खंड–6 में दर्शाए गए दस्तावेज़ों सहित आवेदन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संपदा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार का भौतिक आवेदन या दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उद्योग निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इच्छुक आवेदक योजना के दिशा–निर्देशों 12 नवंबर, 2025 के अनुसार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ये दिशा–निर्देश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदन "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" के अंतर्गत उपयुक्त शीर्षकों के तहत सभी प्रासंगिक विवरणों सहित 20 जनवरी, 2026 को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा किए जाने चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ

श्री विजय पुरम, 7 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस ने 7 जनवरी, 2025 को यहां के कार्बाइन्स कोव तट पर बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन प्रारंभ किया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, अनुशासन तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक (एपीयू) श्रीमती नियति मित्तल कश्यप द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में किया गया।

यह टूर्नामेंट पुलिस की सामुदायिक संपर्क पहलों का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य खेल भावना को प्रोत्साहित करना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा पुलिस और आम जनता के बीच सकारात्मक सहभागिता को सुदृढ़ करना है। नॉकआउट प्रारूप में आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार एवं पदक प्रदान किए जाएंगे। इसमें भागीदारी सभी के लिए निःशुल्क है, जिससे व्यापक सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित होती है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उद्घाटन दिवस पर उत्साहपूर्ण भागीदारी और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जो समुदाय के उत्साह और निष्पक्ष खेल भावना को दर्शाते हैं। अण्डमान तथा निकोबार पुलिस खेल, स्वास्थ्य और सौहार्द को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखे हुए है, तथा यह टूर्नामेंट आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

आर.के. पुर में स्ट्रीट शतरंज आयोजित

हटबे, 7 जनवरी

स्ट्रीट शतरंज पहल सभी उम्र के शतरंज प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। इसी क्रम में, लिटिल अण्डमान में दूसरा कार्यक्रम आज शाम आर. के. पुर बाज़ार में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह आयोजन शिक्षा निदेशालय, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, आर.के. पुर और ग्राम पंचायत आर. के. पुर के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में सभी उम्र के खिलाड़ी शामिल हुए और उत्साही दर्शकों के सामने अपने शतरंज कौशल का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती सुली मंडल, प्रधान, ग्राम पंचायत आर. के. पुर ने किया और समारोहिक प्रथम चाल चली। स्ट्रीट शतरंज न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने का एक सार्थक मंच भी प्रदान करता है।

इससे पहले, स्ट्रीट शतरंज कल हटबे बाज़ार में भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री के. रुद्रामूर्ति, प्रधान, ग्राम पंचायत हटबे ने किया और उन्होंने श्री विद्युत रॉय, प्रधान, ग्राम पंचायत नेताजी नगर के खिलाफ पहला समारोहिक चाल खेला, जबकि श्री विजय कुमार, उप–प्रधान, ग्राम पंचायत हटबे उपस्थित थे। शिक्षा निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शतरंज के माध्यम से यह कार्यक्रम एकता को बढ़ावा देने, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और सभी पीढ़ियों में शतरंज के प्रति उत्साह जगाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ग्राम पंचायत कार्यालय, नमूनाघर, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

F.No: 2-1/GPNG/SA/2025-26/ 445 दिनांक 31.12.2025

प्रधान, ग्राम पंचायत, नमुनाघर, 'ग्राम पंचायत नमुनाघर के सभी वार्डों से घर–घर जाकर अलग–अलग कचरा इकट्ठा करने और उसे नमुनाघर से छोलधारी क्लस्टर तक ले जाने के लिए मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट किराए पर लेने के लिए' ई–टेंडर आमंत्रित करते हैं। यह अवधि (01) एक साल के लिए होगी। टेंडर फॉर्म और अन्य जानकारी वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

Tender ID: 2025_RDPRI_21218_1 प्रधान, ग्राम पंचायत नमूनाघर

देशभर में 50 हजार से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को एनक्यूएएस का प्रमाणन

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देशभर में 50,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) का प्रमाणन मिल चुका है। 31 दिसंबर 2025 तक कुल 50,373 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल इस मानक पर खरे उतर चुके हैं।

यह मानक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, ताकि मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज मिल सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी की गई जानकारी के मुताबिक यह उपलब्धि खासतौर पर गरीब, कमजोर और दूरदराज़ के लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

एनक्यूएएस की शुरुआत साल 2015 में सिर्फ 10 अस्पतालों से हुई थी। पहले इसका ध्यान जिला अस्पतालों पर था लेकिन बाद में इसे उप–जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे प्राथमिक और उप–स्वास्थ्य केंद्रों तक बढ़ा दिया गया।

मौजूदा समय में 48,663 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1,710 बड़े सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र एनक्यूएएस प्रमाणित हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि वर्चुअल जांच (ऑनलाइन मूल्यांकन) शुरू होने से यह काम और तेज हुआ। सिर्फ एक साल में प्रमाणित संस्थानों की संख्या 6,506 से बढ़कर 50,373 हो गई।

सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बिना ज्यादा खर्च के अच्छी और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा मिले। 50,000 एनक्यूएएस प्रमाणन का आंकड़ा पार करना इस बात का प्रमाण है कि भारत मजबूत और आत्मनिर्भर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

मार्च 2026 तक कम से कम 50 प्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को एनक्यूएएस प्रमाणन दिया जाएगा, ताकि देशभर में इलाज की गुणवत्ता एक समान और भरोसेमंद बन सके।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में 55 साहित्यिक कृतियों का किया लोकार्पण

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राजधानी में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रकाशित 55 साहित्यिक कृतियों का लोकार्पण किया। इनमें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित 41 पुस्तकें तथा केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) द्वारा प्रकाशित 13 पुस्तकें और एक तिरुक्कुरल की भारतीय सांकेतिक भाषा (इंडियन साइन लैंग्वेज) श्रृंखला शामिल हैं।

इन प्रकाशनों में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया और तमिल भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शोधपरक कृतियां सम्मिलित हैं। इसके साथ ही तिरुक्कुरल का भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रस्तुतीकरण समावेशी भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रयास देश की भाषायी विरासत को शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र में लाने तथा सांस्कृतिक गौरव को सुदृढ़ करने की व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय भाषाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित सूची में भाषाओं

को शामिल करने से लेकर शास्त्रीय ग्रंथों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन देने तक निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनेक प्रयासों के बावजूद भारतीय भाषाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं।

प्रधान ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भाषायी विविधता इसकी शक्ति है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर को संरक्षित किया जाए तथा भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने दोहराया कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और ये समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं।

सूरत रिवरफ्रंट पर 10 जनवरी को इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, देश–विदेश के 94 पतंगबाज लेंगे भाग

सूरत, 07 जनवरी।

गुजरात के सूरत में आगामी 10 जनवरी को रांदेर जोन स्थित रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव (इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल) का आयोजन होगा। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को लेकर सूरत महानगरपालिका, जिला प्रशासन और गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग व्यापक तैयारियां कर रहा है।

यह पतंग उत्सव गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और सूरत महानगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल अडाजण क्षेत्र में तापी नदी के किनारे स्थित रिवरफ्रंट के समीप रखा गया है। इन तैयारियों के तहत विभिन्न विभागों को अलग–अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पतंग उत्सव में कुल 94 पतंगबाज हिस्सा लेंगे। इनमें 45 अंतरराष्ट्रीय पतंगबाज बहरीन, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों से आएंगे। वहीं देश के 20 पतंगबाज कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल

से भाग लेंगे, जबकि गुजरात से 29 पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन के दौरान अनोखे और आकर्षक पतंगों के करतब दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेंगे। देश–विदेश के पतंगबाजों के साथ–साथ सूरत शहर के खिलाड़ी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक भी इस पतंग उत्सव में शामिल होंगे।

इतिहास के पन्नों में 08 जनवरी : महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग अपने जीवनकाल में ही किंवदंती बन गए

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

स्टीफन हॉकिंग का जन्म 08 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। वे आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान (कॉस्मोलॉजी) और सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान ने विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी।

ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी और समय–स्थान की संरचना को लेकर हॉकिंग के शोध ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उनकी चर्चित पुस्तक 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम पाठकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

गंभीर बीमारी एएलएस (एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) से जूझते हुए भी स्टीफन हॉकिंग ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक सोच से पूरी दुनिया को प्रेरित किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शारीरिक सीमाएं ज्ञान और कल्पना की उड़ान को रोक नहीं सकतीं। स्टीफन हॉकिंग को 13 मानद उपाधियां और अमेरीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की आयु में 14 मार्च, 2018 को निधन हुआ।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1026 – सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसे नष्ट कर दिया।

1790– अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने पहली बार देश को सम्बोधित किया।

1995– समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमये का निधन।

2001– आइवरी कोस्ट में विद्रोह विफल।

2001 – भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम व इंडोनेशिया की सात दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे।

2001 – भारत–वियतनाम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

2008 – केन्द्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया।

2008 – प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

2009 – पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की।

2009 – कोस्टा रिका के उत्तरी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता के भूकम्प में 15 लोगों की मौत एवं 32 अन्य घायल हुए।

2017 – इजराइल के यरुशलम में ट्रक से हमले में कम से कम 4 सैनिकों की मौत, 15 घायल।

2020 – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी।

2020 – भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 'भारत में ई–कॉमर्स पर बाज़ार अध्ययनः महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अवलोकन' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की।

2020 – सीसीआई द्वारा भारत में ई–कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत अप्रैल 2019 में की गई थी।

PRAGATI: जानें तकनीक, जवाबदेही और समन्वय से कैसे बदला भारत का परियोजना शासन मॉडल

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

सार्वजनिक परियोजनाओं में समय और लागत बढ़ने की समस्या किसी एक कारण से नहीं, बल्कि प्रणालीगत खामियों का नतीजा थी। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी, केंद्र–राज्य–स्थानीय सरकारों के बीच तालमेल का अभाव और राज्यों के भीतर विभागीय प्रमुख रहे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI को एक व्यापक, तकनीक–आधारित शासन तंत्र के रूप में परिकल्पित किया।

25 मार्च 2015 को PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे शासन को अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा पर नजर बनाए हुए थी।

PRAGATI का मूल उद्देश्य केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करना रहा है। इसके तीन प्रमुख लक्ष्य तय किए गए– बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर कर उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना, कमजोर प्रदर्शन कर रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के नतीजों में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नागरिक शिकायतों का समाधान। पारंपरिक समीक्षा प्रणालियों से अलग, PRAGATI एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परियोजना निगरानी, शिकायत निवारण और योजना कार्यान्वयन को एकीकृत करता है। इसमें PM GatiShakti, PARIVESH और PM Reference Portal जैसे अहम शासन उपकरण भी शामिल हैं, जिससे रियल–टाइम में प्रगति की निगरानी और समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है।

इस व्यवस्था की सबसे अहम विशेषता यह है कि PRAGATI समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, जिनमें राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के सचिव सीधे तौर पर शामिल होते हैं। सामान्य मुद्दों का समाधान मंत्रालय स्तर पर किया जाता है, जबकि जटिल और अहम मामलों को चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत PRAGATI तक पहुंचाया जाता है।

PRAGATI को पूर्ववर्ती निगरानी तंत्रों से अलग बनाता है इसका सख्त फॉलो–अप और एस्केलेशन मैकेनिज्म। समीक्षा के बाद लिए गए फैसलों की निगरानी कैबिनेट सचिवालय करता है, जबकि योजनाओं और शिकायतों पर मंत्रालय स्तर पर लगातार नजर रखी जाती है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी रहती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फैसले कागजों तक सीमित न रहकर जमीन पर उतरें।

आंकड़े इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं। PRAGATIऔर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) पोर्टल के अनुसार, अब तक 3,300 से अधिक परियोजनाओं की निगरानी की गई है, जिनकी कुल लागत 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही 36 क्षेत्रों से जुड़ी 61 प्रमुख सरकारी योजनाओं और शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कुल 7,735 मुद्दों में से 7,156 का समाधान किया जा चुका है, यानी समाधान दर 90 प्रतिशत से अधिक रही है– जो औसतन हर कार्य दिवस में लगभग एक मुद्दे के समाधान को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा की गई परियोजनाओं में 382 परियोजनाएं शामिल रहीं, जिनमें 637 पैकेज या खंड थे। इनमें उठाए गए 3,187 मुद्दों में से 2,958 का समाधान किया जा चुका है। सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, बिजली तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों की परियोजनाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है– ये वे क्षेत्र हैं, जो ऐतिहासिक रूप से भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और राइट ऑफ वे जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण और वन अथवा पर्यावरण मंजूरी से जुड़े मुद्दे सबसे अधिक सुलझाए गए, इसके बाद निर्माण स्वीकृति, यूटिलिटी अनुमतियां, वित्तीय अड़चनें और कानून–व्यवस्था से जुड़े मामले रहे।

PRAGATI का प्रभाव उन परियोजनाओं में सबसे स्पष्ट दिखाता है, जो वर्षों से अटकी हुई थीं। जम्मू–उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसे 1994 में मंजूरी मिली थी, 2015 से 2020 के बीच PRAGATI समीक्षाओं के जरिए कई अड़चनों से मुक्त हुई। 272 किलोमीटर लंबी इस परियोजना–जिसमें 38 सुरंगें और 943 पुल शामिल हैं, तथा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी मौजूद है–को जून 2025 में चालू किया गया। इसी तरह, 2007 में स्वीकृत नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लंबे समय तक ठप पड़ा रहा। PRAGATI की निगरानी के बाद परियोजना ने रफ्तार पकड़ी और दिसंबर 2025 में इसे कमीशन किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील रेल–सह–सड़क पुल, जिसे 1997 में मंजूरी मिली थी, PRAGATI हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2018 में पूरा हो सका।

PRAGATI के शासन मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक बाहरी अध्ययन में PRAGATI को एक परिवर्तनकारी डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बताया गया। अध्ययन में कहा गया कि इसने वरिष्ठ स्तर पर जवाबदेही को मजबूत किया है और लंबे समय से लंबित बुनियादी ढांचा व सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को गति दी है। अध्ययन ने PRAGATI को रियल–टाइम परियोजना निगरानी के लिए "सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ" बताते हुए इसे सहकारी संघवाद को मजबूत करने वाला और विकासशील देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल करार दिया।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, PRAGATI-PMG इकोसिस्टम के तहत 427 परियोजनाएं ली गईं, जिनमें से 158 पूरी हो चुकी हैं, 266 पर काम जारी है और तीन परियोजनाएं समाप्त की गई हैं। इन परियोजनाओं से जुड़े 1,568 मुद्दों में से 1,437 का समाधान PRAGATI के जरिए किया गया। सरकार का कहना है कि परियोजना क्रियान्वयन के अलावा PRAGATI ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि, अंतर–सरकारी समन्वय में सुधार और शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है।

50 उच्च–स्तरीय समीक्षाओं के साथ PRAGATI अब एक नवाचार से आगे बढ़कर शासन की एक स्थायी संस्था बन चुकी है– जो प्रशासनिक प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय को संस्थागत रूप देती है। जैसे–जैसे भारत बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं में निवेश बढ़ा रहा है, PRAGATI यह सुनिश्चित करने का एक मजबूत आधार बनकर उभरा है कि बड़े लक्ष्य प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पूरे हों।

अमेरिकी वीजा के लिए अब 38 देशों के नागरिकों को 15 हजार डॉलर तक का बॉन्ड देना होगा

काठमांडू, 07 जनवरी।

अमेरिका ने अपने वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम में नेपाल को भी शामिल कर दिया है। अब यात्रियों को अमेरिकी वीज़ा हासिल करने से पहले अधिकतम 15 हजार डॉलर तक का आर्थिक बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है।

अमेरिकी सरकार ने उन देशों की सूची में 25 नए देशों को जोड़ा है, जिनके नागरिकों से बी–1 (व्यापार) या बी–2 (पर्यटन/अत्यावश्यक यात्रा) वीज़ा के आवेदन के समय बॉन्ड जमा करने की मांग की जा सकती है। इन देशों में नेपाल भी शामिल है। अब इस पायलट कार्यक्रम में कुल 38 देश शामिल हो गए हैं।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार नेपाल जैसे देशों के लिए यह नई नीति अगस्त, 2025 में शुरू हुए पायलट प्रोग्राम के तहत 21 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत वीज़ा के इंटरव्यू के दौरान कांसुलर अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि आवेदक को 5,000, 10,000 या अधिकतम 15,000 डॉलर का बॉन्ड देना है या नहीं। आवेदकों को बॉन्ड के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का फॉर्म I–352 पूरा करना होगा और भुगतान अमेरिकी ट्रेज़री विभाग की आधिकारिक ऑनलाइन साइट Pay.gov के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। तीसरे पक्ष की साइटों से भुगतान को सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी।

अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार यह पायलट प्रोग्राम उन देशों को लक्षित करता है, जहां वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहना आम माना जाता है। बॉन्ड जमा करने वाले वीज़ा धारकों को अमेरिका में प्रवेश और निकास केवल निर्दिष्ट एयरपोर्ट्स जैसे बोस्टन लोगन, न्यूयॉर्क का जॉन एफ. केनेडी या वाशिंगटन दुलेस के माध्यम से ही करना होगा।

सर्दियों में अपराजिता की देखभाल कैसे करें? इस तरह फूलों से भर जाएगा पूरा पौधा

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने और धूप कम होने के कारण कई पौधों की ग्रोथ धीमी हो जाती है। इस मौसम में पौधों को अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी अधिक देखभाल की जरूरत होती है। अपराजिता (Clitoria ternatea) ऐसा पौधा है, जो सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन सही पोषण, पानी और धूप की कमी के कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं।

ऐसे में अगर आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ कम हो गई है या पत्तियां पीली होने लगी हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान विंटर केयर टिप्स अपनाकर आप पौधे को दोबारा हरा–भरा बना सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। इससे पौधे पर फिर से भरपूर फूल आने लगेंगे।

सर्दियों के मौसम में कम ही धूप निकलती है। ऐसे में अगर आप पौधे को गमले में लगा रखे हैं, तो इसे छत पर या फिर बालकनी में रख सकते हैं। इससे पौधे को सीधी धूप मिल जाएगी, जिससे पौधा फिर से ग्रोथ करने लगेगा।

ठंड के मौसम में पौधों की मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है। ऐसे में पौधों में पानी डालते समय कुछ खास ध्यान रखना होता है। आप अपराजिता के पौधे में तभी पानी डालें, जब इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी नजर आए। आप सप्ताह में दो बार पानी डाल सकते हैं। हालांकि, पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो।

अपराजिता के पौधे को पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में आप एक माह में एक–दो बार गोबर की खाद, वर्मीकम्पोस्ट या सरसों खली जरूर डालें। इससे पौधे को जरूरी पोषण मिल जाएगा और पौधे पर फूल खिलने लगेंगे।

सर्दियों में पौधे को ठंड से बचाना भी जरूरी होता है। दरअसल, इस दौरान कई जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिससे पौधा खराब भी हो जाता है। ऐसे में रात के समय पौधे को कपड़े से ढक सकते हैं। इससे पौधे पर ठंड का असर कम हो जाएगा।

ठंड में कई बार कीट पौधे को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में आप समय–समय पर नीम तेल का छिड़काव करते रहें। इससे कीट दूर रहते हैं और पौधा हेल्दी बना रहता है।

चुनाव प्रबंधन निकायों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 21–23 जनवरी तक, लोगो जारी

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

चुनाव आयोग 21 से 23 जनवरी तक यहां के भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईसीडीईएम 2026) का आयोजन करने जा रहा है। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सार्थक संवाद को आगे बढ़ाना है।

इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) और इंटरनेशनल आइडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। आज इस संबंध में द्वारका स्थित इंस्टिट्यूट में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसे इंस्टिट्यूट के महानिदेशक राकेश वर्मा ने संबोधित किया।

इस अवसर पर आईआईआईसीडीईएम–2026 का लोगो लॉन्च किया गया। वर्मा ने बताया कि यह लोकतंत्र, सहभागिता, संस्थागत ईमानदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को दर्शाता है। समग्र रूप से यह लोगो एक स्पष्ट संदेश देता है कि लोकतंत्र जनता से संचालित, संस्थानों द्वारा समर्थित और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत की भूमिका केंद्रीय और जिम्मेदार है।

उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता भी संभाली है। इसके तहत यह सम्मेलन वैश्विक लोकतांत्रिक विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरेगा। सम्मेलन का लक्ष्य विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को

सुदृढ़ करना, साझा वैश्विक चुनौतियों पर सामूहिक दृष्टि विकसित करना, श्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों का आदान–प्रदान करना तथा समाधान सह–निर्मित करना है।

वर्मा ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य विषय "समावेशी, शांतिपूर्ण, सुदृढ़ और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र" है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख विषयगत स्तंभ निर्धारित किए गए हैं– भविष्य के लिए लोकतंत्र की पुनर्कल्पना तथा सतत लोकतंत्र के लिए पेशेवर और स्वतंत्र चुनाव प्रबंधन निकायों की अनिवार्यता।

सम्मेलन के दौरान सामान्य और पूर्ण सत्रों के साथ–साथ कई विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें उद्घाटन सत्र, ईएमबी नेताओं की पूर्ण बैठक, ईएमबी कार्य समूह बैठक तथा ईसीआईनेट के शुभारंभ जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक विषयों पर सात सत्र, अंतरराष्ट्रीय चुनावी मानकों पर 11 मॉडल सत्र तथा चुनावी प्रक्रियाओं में 25 श्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे।

'परीक्षा पे चर्चा' के लिए प्रधानमंत्री ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले इस वर्ष के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' को लेकर देशभर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने देश के एग्जाम वॉरियर्स से उनके प्रश्नों, विचारों और अनुभवों को साझा करने का आग्रह किया है, ताकि वे अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकें।

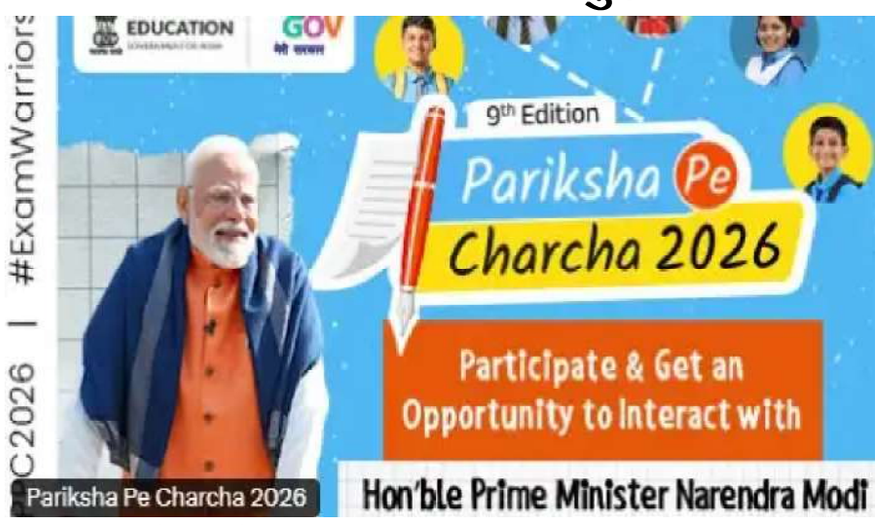

प्रधानमंत्री का छात्रों से संवाद का वार्षिक कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' का यह नौवां संस्करण होगा और यह जनवरी माह में ही आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर संवाद करने को लेकर उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर संदेश साझा करते हुए कहा कि इस संवाद का मुख्य फोकस परीक्षा के तनाव को खत्म करने, शांत और आत्मविश्वासी बने रहने तथा सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा में शामिल होने पर रहेगा। उन्होंने लिखा कि परीक्षाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें बोझ के रूप में नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने देशभर के एग्जाम वॉरियर्स से अपील की कि वे अपने प्रश्नों के साथ–साथ अपने अनुभव भी साझा करें, ताकि उनकी सीख और संघर्ष अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बन सकें। उन्होंने कहा कि छात्रों के वास्तविक अनुभव 'परीक्षा पे चर्चा' को और सार्थक बनाते हैं।

उल्लेखनीय है कि 'परीक्षा पे चर्चा' शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका आयोजन हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं से पहले किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सीधे छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से निपटने, समय प्रबंधन, एकाग्रता और जीवन मूल्यों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वर्ष 2026 में भी इस कार्यक्रम में देशभर से चयनित छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे।

पिछले संस्करणों में 'परीक्षा पे चर्चा' को देश–विदेश के लाखों छात्रों ने लाइव और डिजिटल माध्यमों से देखा–सुना है। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा को भय नहीं बल्कि सीख और आत्मविकास की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना है।

भविष्य के युद्ध के लिए तैयार भारतीय सेना: चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जारी किया प्रशिक्षण विजन दस्तावेज

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

भारतीय सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक महत्वपूर्ण विजन दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जो प्रशिक्षण पद्धति को अधिक आधुनिक, प्रभावी और भविष्योन्मुखी बनाने पर केंद्रित है।

एकीकृत रक्षा स्टाफ (आईडीएस) द्वारा साझा जानकारी के अनुसार, इस दस्तावेज में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य तथा भविष्य की संभावित चुनौतियों का विस्तृत आकलन किया गया है।

इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे सैन्य नेताओं का निर्माण करना है जो आधुनिक युद्धक्षेत्र की जटिलताओं को समझें और जल, थल, वायु, अंतरिक्ष तथा साइबर जैसे विभिन्न डोमेन में मल्टी–डोमेन ऑपरेशन्स को संयुक्त एवं समन्वित रूप से संचालित करने में सक्षम हों।

विजन दस्तावेज में प्रोफेशनल मिलिटरी एजुकेशन के हर चरण के लिए स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य परिभाषित किए गए हैं, ताकि सैन्य अधिकारियों के विकास में क्रमिक और सार्थक प्रगति सुनिश्चित हो सके।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण

से लेकर उच्च अधिकारियों के सामरिक एवं रणनीतिक स्तर के प्रशिक्षण तक सभी स्तरों के लिए अपेक्षित क्षमताओं और दक्षताओं का व्यवस्थित विवरण शामिल है।

यह दस्तावेज न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सशस्त्र बलों को भविष्य की तकनीकी एवं युद्धक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का भी प्रयास करता है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीस ऑफ स्टाफ कमेटी का यह विजन भारतीय सैन्य ढांचे को अधिक समन्वित, सक्षम और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने समुदाय आधारित मल कीचड़ प्रबंधन मॉडलों की सराहना की

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत सभी राज्यों से बातचीत की और समुदाय की मदद से चल रहे मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) के नए मॉडल की तारीफ की।

जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से मंगलवार को आयोजित वर्चुअल संवाद में पाटिल ने कहा कि शौचालय बनाना ही काफी नहीं है, उसे सुरक्षित तरीके से खाली करना, ले जाना, ट्रीट करना और दोबारा इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। ओडिशा के खोरधा जिले में ट्रांसजेंडर समूह द्वारा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) चलाने की पहल को उन्होंने सबसे प्रेरक उदाहरण बताया, क्योंकि इससे सफाई भी हो रही है और लोगों को काम भी मिल रहा है।

संवाद में जलशक्ति राज्यमंत्री वी सोमन्ना, सचिव अशोक केके मीणा और स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण की मिशन निदेशक ऐश्वर्या सिंह भी शामिल हुए। अलग–अलग राज्यों के जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, पंचायत सदस्य और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं और सदस्य भी ऑनलाइन जुड़े।

मंत्रालय ने बताया कि गुजरात के डांग जिले के आदिवासी इलाकों में ट्विन–पिट शौचालय का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। सिक्किम के मंगन जिले में सिंगल–पिट को ट्विन–पिट में बदलने का काम तेजी से किया गया, ताकि एफएसएम के नियम पूरे हो सकें। मध्य प्रदेश के इंदौर की

कालीबिल्लौद ग्राम पंचायत में देश का पहला ग्रामीण एफएसटीपी है, जहां ट्रीट किए पानी में मछली पालन का भी प्रयोग हो रहा है और साथ में एमआरएफ सेंटर भी बनाया गया है। इससे पंचायतों को कमाई का नया जरिया मिला है।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एसएचजी की मदद से क्लस्टर एफएसटीपी मॉडल चलाया जा रहा है, जिसमें रखरखाव की जिम्मेदारी भी स्थानीय समूह संभाल रहे हैं। लद्दाख के लेह जिले में कड़ाके की ठंड और ऊंचाई को देखते हुए इकोसैन शौचालय बनाए गए हैं। त्रिपुरा के गोमती जिले में मेले और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मोबाइल बायो–टॉयलेट लगाए गए हैं, जिन्हें एसएचजी खुद चला रहे हैं और यह मॉडल अपने खर्च खुद निकालने में भी सफल रहा है। संवाद के दौरान लोगों को अपनी बात स्थानीय भाषा में रखने के लिए कहा गया, जिससे समुदाय के लोग खुलकर अपने अनुभव बता सके।

एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग अब ओएनडीसी नेटवर्क पर लाइव

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण Archaeological Survey of India (ASI) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स Open Network for Digital Commerce (ONDC) पर 170 से ज़्यादा केंद्र संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।

यह पहल एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों तक डिजिटल पहुंच को बहुत बढ़ाती है। इससे भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए देश के कुछ सबसे मशहूर विरासत स्थलों और संग्रहालयों के प्रवेश टिकट कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आसानी से बुक करना आसान हो जाता है।

एएसआई के टिकटिंग सिस्टम को ओपन डिजिटल नेटवर्क पर एकीकृत करके, नागरिक और पर्यटक अलग–अलग एप्लिकेशन के ज़रिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहुंच और सुविधा बेहतर होती है, साथ ही इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम के ज़रिए सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शी और कुशल डिलीवरी मज़बूत होती है।

ओएनडीसी–इनेबल्ड एप्लिकेशन के ज़रिए एएसआई स्मारकों के लिए टिकट बुक करने वाले पर्यटक मौजूदा सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों

के लिए 5 रूपए और विदेशी नागरिकों के लिए 50 रूपए की छूट शामिल है।

दरअसल, ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटक स्मारकों और संग्रहालयों में फिजिकल टिकट की कतारों से बच सकते हैं, जिससे तेज़ी से और आसानी से एंट्री सुनिश्चित होती है। इस इंटीग्रेशन को एनडीएमएल (NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड) ने तकनीकी रूप से संभव बनाया है, जिसने एएसआई के स्मारकों और संग्रहालयों की पूरी इन्वेंट्री को ओएनडीसी नेटवर्क पर जोड़ा है।

इसके अलावा, टिकट Highway Delite (वेब, Android और iOS), Pelocal के WhatsApp–आधारित टिकटिंग अनुभव (यूज़र +91 84228 89057 पर "Hi" भेजकर बुकिंग शुरू कर सकते हैं)। यह Abhee by Mondee (Android और iOS) जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। कई और कंज्यूमर–फेसिंग एप्लिकेशन ओएनडीसी नेटवर्क के साथ एकीकरण के अलग–अलग चरणों में हैं।

नई दिल्ली में 'आवाज़ों के जुगनू' का आज होगा लोकार्पण

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने रिकॉर्डेड इंटरव्यू और प्रामाणिक प्रकाशन के ज़रिए भारत की मशहूर आवाज़ों के दस्तावेज़ीकरण और उन्हें सुरक्षित रखने की एक ख़ास पहल की है। इसे गुरुवार, 8 जनवरी को किताब और ऑडियो, दोनों फॉर्मेट में लोकार्पित किया जाएगा। इसका शीर्षक है– 'आवाज़ों के जुगनू'।

आईजीएनसीए के मुताबिक समवेत सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर और वॉइस एक्टर हरीश भिमानी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर और वॉइस एक्टर शम्मी नारंग, जबकि विशेष अतिथि के रूप में वॉइस एक्टर सोनल कौशल कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करेंगे। आईजीएनसीए के मीडिया नियंत्रक अनुराग पुनेठा स्वागत वक्तव्य देंगे, जबकि पुस्तक की संयोजन एवं संकलनकर्ता डॉ. शेफाली चतुर्वेदी पुस्तक के बारे में जानकारी देंगी।

आईजीएनसीए के मुताबिक इस पुस्तक में ऑल इंडिया रेडियो, एफएम चैनल, वॉइसओवर इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग और मंचीय कविता परम्परा से जुड़े 31 लोगों की यात्रा के बारे में बताया गया है।

जनवरी में घूमने की बेस्ट जगहें, परिवार या दोस्तों के साथ बनाएं जाने का प्लान, बर्फबारी भी देख पाएंगे

नई दिल्ली, 07 जनवरी।

जनवरी के महीने में अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं और कोई अच्छी जगह की तलाश में हैं तो जरा ब्रेक लेकर यह आर्टिकल पढ़ें। इससे आपको प्लान बनाने में काफी मदद मिलेगी। यहां हम भारत के उन डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप इस महीने एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनवरी में यह जगहें अन्य महीनों की तुलना में ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। इन सभी जगहों पर कहीं मौसम आपको ठंडा मिलेगा, तो कहीं सुहावना। साथ ही कुछ जगहों पर आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती हैं।

जनवरी के महीने में आप गुलमर्ग घूमने जा सकते हैं। यहां आमतौर पर जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी होती है। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं तो आपको यहां जाना चाहिए। हिमालय में 2,650 मीटर की ऊंचाई पर यह बसा हुआ है। यहां आपको बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार नजारा देखने को मिलेगा।

अगर आप बहुत ज्यादा सर्दी या बर्फबारी वाली जगह पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जैसलमेर जाना चाहिए। जनवरी में यहां का मौसम घूमने के लिए परफेक्ट होता है। यहां दिन में आपको हल्की धूप मिलेगी लेकिन रातें सर्द होंगी। यहां आप डेजर्ट सफारी, लोक संगीत, ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं।

जनवरी के महीने में घूमने के लिए कच्छ का रण भी बेहतरीन ऑप्शन है। यहां का लोकनृत्य, हस्तशिल्प, संगीत और टेंट सिटी आपको लुभाएगा। इतना ही नहीं फुल मून नाइट पर सफेद नमक की जमीन पर पड़ती चांदनी देखने के लिए भी आप यहां जा सकते हैं।

कुफरी शिमला के पास स्थित एक और ऊंचा टूरिस्ट स्पॉट है। यहां जनवरी के महीने में बर्फबारी होती है। यहां पहुंचने के बाद आप स्लेज राइड और स्नोबॉल फाइट का लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं स्नो गेम्स, स्नोबॉल फाइट भी इंजॉय कर सकते हैं।

इसे भारत की 'स्कीइंग की राजधानी' कहा जाता है। यहां भी जनवरी में बर्फबारी होती है। उत्तराखंड में 2,800 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत शहर देश के सबसे अच्छे नेचुरल स्कीइंग स्लोप्स के लिए जाना जाता है।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बन कर तैयार, आरडीएसओ ने शुरू किये अंतिम परीक्षण

जींद, 07 जनवरी।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो गयी है और इसे पटरी पर उतारने से पहले रेलवे की तकनीकी टीम ने मानकों के आधार पर अंतिम परीक्षण शुरू कर दिये हैं।

लखनऊ स्थित रेलवे के अभिकल्प, विकास एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के तकनीकी अधिकारी फिलहाल ट्रेन संचालन को लेकर हर बारीक पहलू पर काम कर रहे हैं। इस विशेषज्ञ टीम ने ट्रेन की टेस्टिंग की। टीम का मुख्य फोकस पावर कार और उससे जुड़े सुरक्षा एवं नियंत्रण उपकरणों पर रहा। स्पीड सेंसर, कंट्रोल सिस्टम को अलग–अलग गति पर परखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। टेस्टिंग के दौरान ट्रेन को धीमी और मध्यम गति पर चला कर उपकरणों की कार्यक्षमता को रिकार्ड किया गया। इसके अलावा ट्रेन के पायदानों की मजबूती और ऊंचाई की भी जांच की गई।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस ट्रेन को ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में स्थापित किए गए हाइड्रोजन प्लांट को अंतिम कमीशनिंग एवं नियमित संचालन के दौरान स्थिर और निर्बाध 11 केवी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्लांट की वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति, बैकअप व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। इसके लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी सु.ढ़ रखा जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के लिए जींद में तीन हजार किलोग्राम भंडारण क्षमता का देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जो अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है। यह प्लांट 24 घंटे आधार पर संचालित होगा।